

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 585वीं बैठक दिनांक 13/07/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, सदस्य ।
6. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
7. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
8. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 8307/2021 Smt. Sangeeta Patidar W/o Shri Sudama Patidar, 49, Happy Villa Colony, Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (19400 cum per annum) (Khasra No. 496/3/2), Village - Bolda, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP) EIA Consultant-M/s Apex Mintech, Udaipur.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 496/3/2), Village - Bolda, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 493वीं दिनांक 23/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है ।

प्रकरण सेक की 585वीं बैठक दिनांक 13/07/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 जुलाई 2022

- 2. प्रकरण क्रमांक 9043/2022 - श्री संजय मित्तल, ओनर, 11-12 दून मार्केट, जबलपुर रोड वरगावाँ, जिला कटनी (म.प्र.) डोलोमाईट एवं क्वार्ट्ज माइन, खसरा नं. 135, 136, रकबा 4.00 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता डोलोमाईट एवं क्वार्ट्ज (Average) - 3,01,999.40 टीपीए, ग्राम वडागाँव, तहसील बडवरा जिला कटनी (म.प्र.) EIA Consultant - M/s Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP., Gurugram, Haryana.**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आन लाईन प्राप्त यह प्रकरण डोलोमाईट एवं क्वार्ट्ज उत्खनन का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 135, 136, रकबा 04.00 हेक्टेयर, ग्राम वडागाँव तहसील बडवरा जिला कटनी (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 493वीं दिनांक 23/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 13/07/22 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आकाश गोयल, माइन मेनेजर और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, मेसर्स अमलतास इंनवायरो इण्ड. कंसल्टेंट, गुरुग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए (विस्तृत जानकारी फार्म-02 के बिंदु क्रमांक-38 पर दर्ज है)। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान क्षेत्र में कई पेड़ लगे हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान में कुल 06 पेड़ लगे हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि गूगल इमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि 06 से अधिक पेड़ खनन क्षेत्र में लगे हैं तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जो फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं, उसमें से एक पेड़ पलाश का दिख रहा है, जो इवेंट्री में शामिल नहीं है। इसी प्रकार ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न फोटोग्राफ के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि गर्थ मेजरमेंट का तरीका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि गर्थ मेजरमेंट चेस्ट हाईट या जमीन से 1.37 मीटर की ऊँचाई पर की जानी चाहिए, अतः ट्री-इवेंट्री उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित की जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूरी पर सड़क है तथा पूर्व दिशा में 435 मीटर पर तालाब हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान तालाब का गहरीकरण, खदान के चारों ओर फेंसिंग, गाँव में पानी व लाईट की समस्या तथा वृक्षारोपण कार्य किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये अतिरिक्त टॉर बिंदुओं का सारगर्भित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जैसे : खदान के पश्चिम दिशा में 100 मीटर दूरी पर सड़क होने के कारण प्रोटेक्शन प्लॉन पूछा गया था जिसका उत्तर संतोषजनक नहीं है। इसी प्रकार फार्म-2 एवं ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत जानकारियों में कई बिंदुओं पर भिन्नता पाई गई, जिसके संदर्भ में समिति द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार को त्रुटियाँ बताई गई तथा उनके द्वारा किये गये कार्य के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त की गई। पर्यावरणीय सलाहकार ने त्रुटियों के लिए खेद व्यक्त

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

किया तथा प्रस्तावित किया कि वे पुनरीक्षित जानकारी सुधार कर प्रस्तुत कर देंगे तथा भविष्य में पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखेंगे। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने, फार्म-2 एवं ई.आई.ए. रिपोर्ट में निम्न बिंदुओं पर संशोधन/सुधार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-01 में फर्म का नाम Badagaon Dolomite Quartz Quarry Mining Project दिया गया है जबकि टॉर मेसर्स बालाजी मार्बल एवं टाईल्स प्रा.लि. के नाम से जारी हुआ है, अतः स्थिति स्पष्ट की जाये कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-16 एवं 16.1 में कोई जानकारी नहीं दी गई है जबकि बिंदु क्रमांक-15 में जल की आवश्यकता 4.63 किलोलीटर/दिन दर्शाई है, अतः स्थिति स्पष्ट करें।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-17 में कोई जानकारी नहीं दी गई है तथा मोड आफ डिस्पोजल भी त्रुटिपूर्ण है।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-18.1(3) में एनओएक्स की इंकीमेंटल कांसनट्रेशन की जानकारी त्रुटिपूर्ण है।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-19 में 04 केव्हीए के सोलर पॉवर का प्रस्ताव दिया गया है, अतः इसे ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-20 में 04 हे. निजी भूमि का विवरण दर्ज है जो परियोजना प्रस्तावक के नाम से नहीं है, अतः भू-स्वामी की सहमति प्रस्तुत की जाये।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-25(बी) में ट्री-इंवेन्ट्री अपलोड नहीं की गई है तथा निल बताई गई है किंतु ई.आई.ए. रिपोर्ट में एजेज्जर-18 में 06 पेड़ों की ट्री-इंवेन्ट्री बताई गई है जबकि गूगल इमेज अनुसार पेड़ों की संख्या ट्री-इंवेन्ट्री में दर्शायी गई पेड़ों की संख्या से बहुत अधिक है अतः ट्री-इंवेन्ट्री पूर्ण नहीं है। ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ जो फोटोग्राफ प्रस्तुत किये गये हैं, उसमें से एक पेड़ पलाश का दिख रहा है, जो इंवेन्ट्री में शामिल नहीं है तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ संलग्न फोटोग्राफ के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि गर्थ मेजरमेंट का तरीका त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि गर्थ मेजरमेंट चेस्ट हाईट या जमीन से 1.37 मीटर की ऊँचाई पर की जानी चाहिए तथा जानकारी सेंटीमीटर में अंकित की जानी चाहिए। अतः ट्री-इंवेन्ट्री उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में पुनरीक्षित की जाये।
- ✓ फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-38 (x) में प्रस्तुत कंसल्टेंट का एकीडेशन दिनांक 06/07/22 तक ही है, अतः वैध कंसल्टेंट एकीडेशन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।
- ✓ प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये अतिरिक्त टॉर बिंदुओं का सारगर्भित उत्तर (जैसे 02,07,10,11,1,2,14) प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः दिये गये अतिरिक्त टॉर के सभी बिंदुओं का सारगर्भित उत्तर प्रस्तुत किया जाये।
- ✓ ई.आई.ए. पेज नं. 11/1 के बिंदु क्रमांक-14 में यह उल्लेखित है कि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित नहीं है जबकि फार्म-2 के बिंदु क्रमांक-14.6 में भू-जल स्तर 30 मीटर तथा बिंदु

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 जुलाई 2022

क्रमांक-35 (11) में खनन की गहराई 30 मीटर दर्शाई गई है । अतः यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित नहीं है ।

- ✓ प्रकरण के साथ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2016 की है, अतः सिया की 724वीं बैठक दिनांक 17/05/22 में लिए गए निर्णयानुसार कटनी जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खनन क्षेत्र की स्थिति तथा कटनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति ।

3. Case No 9258/2022 M/s Akash Granite, R/o Indira Nagar, Karbai, Dist. Mahoba, UP - 210424 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (1,20,000 cum per annum) (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) Environment Consultant : Globus Environment Engineering Service, Lucknow.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 499), Village - Ghatahari, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 584वीं बैठक दिनांक 05/07/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

आज दिनांक 13/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिनेश चन्द्र गुप्ता (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री आनंद गुप्ता, मेसर्स ग्लोबस इंनवायरमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ, (उ.प्र.) उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. प्रस्तुत की गई । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2474 दिनांक 29/07/2021 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 19.105 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लान के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर शेड है, पश्चिम दिशा में 280 मीटर पर रोड़ तथा दक्षिण दिशा में 300 मीटर पर मंदिर है अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें। प्रश्नाधीन खदान बीच से खुदी हुई दिख रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खुदी होने के कारण टॉर वॉयलेशन प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान का मध्य भाग खुदा हुआ है जहाँ पर गूगल इमेज अनुसार खनन कार्य वर्ष 2014 से 2020 तक बिना पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के खनन कार्य किया गया है।

After deliberation, Committee considering the recent GoI, MoEF & CC, OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 recommends that case may be dealt as per the provisions laid down in this notification and the project may granted Terms of Reference for undertaking Environment Impact Assessment and preparation of Environment Management Plan on assessment of ecological damage, remediation plan and natural and community resource augmentation plan and it shall be prepared as a independent chapter in the EIA report by the accredited consultant and the collection and analysis of data for assessment of ecological damage, preparation of remediation plan and natural and community resource augmentation plan shall be done by an environmental laboratory accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

Committee recommends SEIAA to initiate action under section 15 of the Environment (Protection) Act, 1986 through competent authority as per step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.

Committee also recommended to issue additional TOR as per OM F. No. 22-21/2020-IA.III dated 07.07.2021 & Notification S. O. 1030 (E), dated 8th March, 2018 along with standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's and as per Annexure-D:-

1. Project description, its importance and the benefits.
2. Some Shed (on 90 meters SW) are observed in the western side of the lease PP shall discussed their protection plan with their clear status and photos that what for these sheds are constructed and what is their present use.
3. Similarly, protection plan for temple at 300 meters on northern side and road on north-west side at a distance of 100 meters shall also be discussed in the EIA report.
4. Inventory of all existing trees with their girth and height details and if any tree is to be uprooted, then its proper management plan it should be clearly addressed in EIA.
5. Project site detail (location, toposheet of the study area of 10 Km, coordinates, Google map, layout map, land use, geological features and geo-hydrological status of the study area, drainage.

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 जुलाई 2022

6. Proposal for rain water harvesting and river rejuvenation shall be submitted through an expert considering aquifer, percolation tank, recharge shaft and sub-surface dyke with EIA report.
7. Forest and Wildlife and eco-sensitive zones, if any in the study area of 10 Km Clearances required under the Forest (Conservation) Act, 1980, the Wildlife (Protection) Act, 1972 and/or the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Baseline environmental study for ambient air (PM10, PM2.5, SO₂, NO_x & CO), water (both surface and ground), noise and soil for one month (except monsoon period) as per MoEF & CC/CPCB guidelines at minimum 6 locations in the study area of 10 Km.
9. Details on flora and fauna and socio-economic aspects in the study area.
10. Likely impact of the project on the environmental parameters (ambient air, surface and ground water, land, flora and fauna and socio-economic, etc.).
11. Source of water for different identified purpose with the permissions required from the concerned authorities, both for surface water and the ground water (by CGWA) as the case may be, Rain water harvesting, etc.
12. Waste water management (treatment, reuse and disposal) for the project and also the study area.
13. During EIA study, 04 to 05 trial pits (out of which one shall be in the barrier zone of the lease area) shall be dugged and soil profile be studied for proposing plantation as per the soil quality.
14. PP shall also submit the year wise details of mineral excavated with credible proof of royalty deposited from competent authority.
15. PP shall provide an elaboration of the cost benefit analysis in terms of loss of natural resources and nearby vegetation area, agricultural area vs mineral benefit along with eco-system services such as soil loss, water percolation, fodder availability, habitat loss and flora & fauna due to mining.
16. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the Environmental (Protection) Act, 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or a laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.
17. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural community resource augmentation plan corresponding to the ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
18. The details as per step 12 of MoEF&CC OM dated 07/07/21 shall be furnished with EIA report with credible documentary evidences.

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला - छतरपुर (रेत खनिज) (संशोधित).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (सिया) से प्राप्त संशोधित (Rivesed) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी, जिसमें खनिज विभाग, छतरपुर की ओर से श्री अमित मिश्रा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुये थे। उक्त संदर्भित बैठक में समिति ने विस्तृत चर्चा एवं रिपोर्ट का विस्तृत विश्लेषण कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुरूप सभी बिंदुओं की जानकारी अद्यतन कर प्रस्तुत करने के निर्देश जिला खनिज अधिकारी को दिये थे।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्राधिकरण समाघात प्राधिकरण (SEIAA) ने दिनांक 05/07/2022 को ई-मेल के माध्यम से पुनः संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) को परीक्षण हेतु सॉफ्ट कॉपी भेजी गई है। जिला कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर, म.प्र. के पत्र क्र०. 1516 दिनांक 30/06/2022 के माध्यम से पुनः संशोधित रेत खनिज की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) की हार्ड कॉपी प्रेषित की गयी थी। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सेक समिति की सदस्यों दिनांक 08/06/2022 को सॉफ्ट कॉपी अवलोकन एवं मतांकन हेतु प्रेषित की गई। उक्त संशोधित डी.एस.आर. पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 585 वीं बैठक दिनांक 13/07/2022 में प्रस्तावित की गई है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 585 वीं बैठक दिनांक 13/07/22 में छतरपुर जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान खनिज विभाग छतरपुर की ओर से श्री अमित मिश्रा विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुये। चर्चा के दौरान समिति ने पाया कि प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज हेतु है, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुरूप जानकारी को अद्यतन कर प्रस्तुत किया गया है। समिति ने पाया कि छतरपुर जिले की यह संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) पूर्व में जिला समिति (बैठक दिनांक 18/05/22) से अनुमोदित है तथा 30 दिवस तक जिले के पोर्टल पर दावा/आपत्ति हेतु रखी जा चुकी है। समिति ने पाया कि समिति द्वारा पूर्व की बैठकों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सुधार हेतु जो सुझाव दिये गये थे (जैसे माइनेबल मिनरल पोटेन्शियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेन्शियल लीजवार विवरण की जानकारी निर्धारित प्रपत्र साथ ही स्वीकृत 48 रेत खदानों के कोर्डिनेट्स (Co-ordinates) के अनुसार लीजवार गूगल (KML Files) CD) में सुधार कर संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) प्रस्तुत की गयी है।

चर्चा उपरांत समिति ने यह अनुशंसा है कि खनिज अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला छतरपुर ने पत्र क्रमांक 1516/खनिज/2022, दिनांक 30/06/22 के माध्यम से “माइनेबल मिनरल पोटेन्शियल” (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेन्शियल) लीजवार विवरण की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है अतः संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाये गये लेट-लॉग की जांच गूगल इमेज से कर पुष्टि कर ली जाये तथा जानकारी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाये।

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 जुलाई 2022

5. Case No 9255/2022 Shri Rajat Choudhary, Lessee, 424, Village - Hridaypur, Damoh Khas, Dist. Damoh, MP - 470661, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.589 ha. (16500 cum per annum) (Khasra No. 114/1, 115/1) Village - Mandharpur, Tehsil - Buxwaha, Dist. Chhatarpur, MP

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 114/1, 115/1) Village - Mandharpur, Tehsil - Buxwaha, Dist. Chhatarpur, (MP) 1.589 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 584वीं बैठक दिनांक 05/07/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 13/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री रजत चौधरी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1342 दिनांक 30/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान में कई पेड़ लगे हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान में सागौन के 12 पेड़ लगे हैं, किंतु इसमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जायेगा तथा जिस क्षेत्र में पेड़ लगे हैं, उसे नॉन माइनिंग क्षेत्र छोड़ा गया है, जिसे प्रस्तुतीकरण में दिखाया गया है। इसी प्रकार के उत्तरी भाग से 50 मीटर की दूरी पर एच.टी. लाईन निकल रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एच.टी. लाईन 55 मीटर की दूरी पर है तथा 7.5 मीटर का बैरियर जोन छोड़ने के बाद खनन क्षेत्र से लगभग 60 मीटर की दूरी पर हो जाती है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

✓ समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना।

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 जुलाई 2022

- ✓ प्रकरण के साथ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पुरानी है, अतः सिया की 724वीं बैठक दिनांक 17/05/22 में लिए गए निर्णयानुसार छतरपुर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खनन क्षेत्र की स्थिति तथा छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति ।

6. Case No 8624/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.082 ha. (70000 cum per annum) (Khasra No. 1214, 1215), Village - Pasan, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1214, 1215), Village - Pasan, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 6.082 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 585वीं दिनांक 13/07/22 एवं 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । समिति ने पाया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा यह लेख किया गया था कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई अनुशांसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । आज दिनांक तक अनूपपुर जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है तथा बिना अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के रेत खनन संबंधी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर अनुशांसा नहीं की जा सकती है । अतः जब तक संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं होता तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों को डिलिस्ट किया जाये, ताकि ऐसे प्रकरण सिया/सेक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित परिलक्षित न हो ।

इस प्रकरण में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ले जा रही है। अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण को उपरोक्त आधार पर नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

7. Case No 8625/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Signatory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 164), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 164), Village - Cholna, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 6.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 585वीं दिनांक 13/07/22 एवं 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति ने पाया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा यह लेख किया गया था कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। आज दिनांक तक अनूपपुर जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है तथा बिना अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के रेत खनन संबंधी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर अनुशंसा नहीं की जा सकती है। अतः जब तक संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं होता तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों को डिलिस्ट किया जाये, ताकि ऐसे प्रकरण सिया/सेक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित परिलक्षित न हो।

इस प्रकरण में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 जुलाई 2022

कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है । अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण को उपरोक्त आधार पर नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

8. Case No 8626/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Sigantory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.50 ha. (32000 cum per annum) (Khasra No. 1763, 95/1), Village - Gobri, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1763, 95/1), Village - Gobri, Tehsil - Jaithari, Dist. Anuppur (MP) 6.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 585वीं दिनांक 13/07/22 एवं 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । समिति ने पाया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा यह लेख किया गया था कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । आज दिनांक तक अनूपपुर जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है तथा बिना अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के रेत खनन संबंधी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर अनुशंसा नहीं की जा सकती है । अतः जब तक संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं होता तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों को डिलिस्ट किया जाये, ताकि ऐसे प्रकरण सिया/सेक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित परिलक्षित न हो ।

इस प्रकरण में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है । अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण को उपरोक्त आधार पर नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 जुलाई 2022

9. Case No 8627/2021 M/s K.G.Developers, Shri Ashish Kharya, Authorised Signatory, C-99, New Minal Residency, J.K.Road, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.664 ha. (67968 cum per annum) (Khasra No. 1), Village - Chakaghat, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) Env. Consultant Aseries Envirotek India Pvt. Ltd., Lucknow U.P.

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1), Village - Chakaghat, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) 5.664 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

प्रकरण आज बैठक क्रमांक 585वीं दिनांक 13/07/22 एवं 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। समिति ने पाया कि राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई तथा यह लेख किया गया था कि अनूपपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई अनुशांसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। आज दिनांक तक अनूपपुर जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अप्राप्त है तथा बिना अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के रेत खनन संबंधी पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों का परीक्षण कर अनुशांसा नहीं की जा सकती है। अतः जब तक संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं होता तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों को डिलिस्ट किया जाये, ताकि ऐसे प्रकरण सिया/सेक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित परिलक्षित न हो।

इस प्रकरण में समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रुचि नहीं ली जा रही है। अतः समिति की अनुशांसा है कि इस प्रकरण को उपरोक्त आधार पर नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाये।

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 13 जुलाई 2022

10. Case No 9196/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.10 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 1), Village - Kutiya, Tehsil - Rajnagar, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1), Village - Kutiya, Tehsil - Rajnagar, Dist. Chhatarpur (MP) 2.10 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 13/06/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 489 दिनांक 26/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह रेत खदान बने नदी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है तथा अनुमोदित खनन योजना के "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि गूगल इमेज के अनुसार खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 300 मीटर की दूरी पर स्टॉप डेम स्थित है तथा स्वीकृत खदान स्टॉप डेम के डाऊन स्ट्रीम में है अतः 200 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाये तथा पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत किया जाये। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है उसके तालिका (पेज न. 70) क्रमांक-35 में यह खदान दर्शित है जिसमें मानसून के पश्चात् 63,000 घनमीटर रेत की मात्रा दर्शाई गई है तथा डी.एस.आर. के तालिका-27 (पेज न. 81) के अनुसार "माईनेवल मिनरल पोर्टेशियल - कुल मिनरल पोर्टेशियल का 60 प्रतिशत" 37,800 घनमीटर है जो पर्यावरणीय

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

अभिस्वीकृति हेतु आवेदित मात्रा 10,000 घनमीटर से अधिक है । समिति द्वारा पूछे जाने पर परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज हेतु) का अभी अनुमोदन नहीं हुआ है किंतु नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज हेतु) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- खदान के उत्तर-पश्चिम दिशा में 300 मीटर की दूरी पर स्टॉप डेम स्थित है तथा स्वीकृत खदान स्टॉप डेम के डाऊन स्ट्रीम में है अतः 200 मीटर का सेट-बैक दिखाते हुए पुनरीक्षित सरफेस मैप प्रस्तुत करें।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. ।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना ।

11. Case No 9197/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 4.0 ha. (35000 Cum per annum) (Khasra No. 1400), Village - Sadkar, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1400), Village - Sadkar, Tehsil - Chandla, Dist. Chhatarpur (MP) 4.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 13/06/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 489 दिनांक 26/04/22

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह रेत खदान केन नदी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है तथा अनुमोदित खनन योजना के "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो नई डी.एस.आर. उनके द्वारा अपलोड की गई है उसके तालिका (पेज न. 70) क्रमांक-30 में यह खदान दर्शित है जिसमें मानसून के पश्चात् 1,20,000 घनमीटर रेत की मात्रा दर्शाई गई है तथा डी.एस.आर. के तालिका-27 (पेज न. 80) के अनुसार "माईनेवल मिनरल पोर्टेंशियल - कुल मिनरल पोर्टेंशियल का 60 प्रतिशत" 72,000 घनमीटर है जो पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु आवेदित मात्रा 35,000 घनमीटर से अधिक है। समिति द्वारा पूछे जाने पर परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छतरपुर जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज हेतु) का अभी अनुमोदन नहीं हुआ है किंतु नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज हेतु) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :-

- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित पौधारोपण योजना।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी.।
- समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर योजना।

12. Case No 9198/2022 M/s Euphoria Mines & Minerals, Partner, Shri Himanshu Meena, 9A, Paramount Villa, Near Ansal, Shamla Hills, Bhopal - 462013 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 1.40 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 701), Village - Rampur Kurra, Tehsil - Chhatarpur, Dist. Chhatarpur (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 701), Village - Rampur Kurra, Tehsil - Chhatarpur, Dist. Chhatarpur (MP) 1.40 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 583वीं बैठक दिनांक 30/06/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे।

आज दिनांक 13/06/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री हिमांशु मीणा, पार्टनर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामविशाल शुक्ला, मेसर्स एसीरिज इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे : लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन योजना, खसरा पंचशाला, फार्म-2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 489 दिनांक 26/04/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

यह रेत खदान तरपर नदी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण अनुमोदित खनन योजना में वर्णित है तथा अनुमोदित खनन योजना के "रिप्लेनिशमेंट प्लान" के अनुसार रेत की चाही गई मात्रा रिप्लेनिश हो रही है जिसका अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है। बैठक के दौरान समिति ने यह पाया कि गूगल इमेज के अनुसार खदान के दक्षिण-पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी पर रेल्वे पुल स्थित है तथा स्वीकृत खदान पुल के डाऊन स्ट्रीम में है, अतः इन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईड लाईन फॉर सेंड-2020 के अनुसार कम से कम 1000 मीटर का सेट-बैक छोड़ा जाना आवश्यक है। समिति ने पाया कि 1000 मीटर का सेट-बैक छोड़ने के बाद उत्खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होगा, अतः ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की अनुशंसा नहीं है, अतः प्रकरण को आगामी कार्यवाही हेतु सिया को अग्रेषित किया जाये।

- 13.** समिति को अवगत कराया गया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण की 735वीं बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वीं बैठक दिनांक 12/7/22 के कार्यवाही विवरणों में अधिकांश प्रकरणों जो सेक द्वारा अनुशंसित कर प्रेषित किये गये थे, को प्राधिकरण द्वारा सेक को पुनः अग्रेषित किया गया है जिसमें परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी ऑफ लाईन के स्थान पर ऑनलाईन प्राप्त की जाये, प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार का नाम अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अंकित किया जाये तथा जिन प्रकरणों में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित नहीं है, उन प्रकरणों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा के पश्चात् सिया को प्रेषित किया जाये आदि निर्देश जारी किए गए हैं।

समिति ने चर्चा में अनुशंसा की कि जिन जिलों के प्रकरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के कारण सिया द्वारा सेक को पुनः अग्रेषित किये गये हैं, उन जिलों के जिला कलेक्टर एवं जिला खनिज अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट/अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

बावत् सेक स्तर से पत्र जारी किये जाये ताकि प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर मतांकन कर सिया को अविलम्ब प्रेषित की जा सके । समिति ने पाया कि सिया ने सभी जानकारी ऑनलाईन प्राप्त करने के निर्देश दिए है । सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” की आवधारणा के तहत त्वरित एवं समय-सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की जानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की जाती है । जो परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण के पश्चात् वांछित जानकारी प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनसे जानकारी परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार पर्यावरणीय सलाहकार के फर्म के विवरण भी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन फार्म-02 में उपलब्ध होते हैं ।

चूँकि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण की 735वी बैठक दिनांक 11/7/22 तथा 736वी बैठक दिनांक 12/7/22 के कार्यवाही विवरणों के अनुसार जानकारी परियोजना प्रस्तावक से ऑनलाईन प्राप्त की जानी है, अतः इस बावत् इस बावत् सिया द्वारा सेक को पुनः अग्रेषित सभी प्रकरण सेक की आगामी बैठक के एजेंडा में लेकर उनपर चर्चा कर समुचित निर्णय लिया जाये ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murram and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

37. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.

8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{\text{th}}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - i. Minable Potential of sand mine.
 - j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - k. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
- i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई –
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक ।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई ।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना ।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है ।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - I. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- पौधों की ऊँचाई/गोलाई -

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माइनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड साइड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

585वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 13 जुलाई 2022

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।
- नोट 4 :-** पौधों की ऊँचाई/गोलाई -
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) बनाना तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई।		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
39. The consent of Gram Sabha of the villages in the area where project is proposed shall be obtained